



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 843 राँची, मंगलवार 10 अग्रहायण, 1937 (श०)
1 दिसम्बर, 2015 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

23 नवम्बर, 2015

संख्या-एल0जी0-27/2015-140--लेज0 झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर राज्यपाल दिनांक 7 नवम्बर, 2015 को अनुमति दे चुके हैं इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2015

(झारखंड अधिनियम, 21, 2015)

झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 (अंगीकृत) में संशोधन हेतु अधिनियम

प्रस्तावना:-

1- चूँकि सहकारी समितियों का स्वैच्छिक संस्था के रूप में गठन के साथ सदस्यों के सामाजिक एवं आर्थिक बेहतरी के लिए सदस्यों की आर्थिक सहभागिता, सदस्यों के जनतांत्रिक नियंत्रण एवं स्वायत्त कार्यकलाप से समितियाँ अपने सदस्यों के हित में और अधिक सार्थक रूप में कार्य कर सकेंगी;

और चूँकि राज्य सरकार का यह दायित्व है कि वह राज्य में सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्यकलाप, जनतांत्रिक नियंत्रण एवं व्यावसायिक प्रबन्धन को प्रोत्साहित करे एवं उसका उन्नयन करे और इस ओर ऐसे कदम उठाये जिनकी इस उद्देश्य हेतु आवश्यकता हो;

और चूँकि संविधान के सन्तानवें संशोधन अधिनियम, 2011 के आलोक में झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 में कई संशोधन आवश्यक हैं;

भारत गणराज्य के 66वें वर्ष में झारखण्ड राज्य के राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:-

(i) यह अधिनियम झारखण्ड सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जा सकेगा।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. अधिनियम 6, 1935 की धारा-2 की उपधारा-(खख) के बाद अन्तःस्थापन। -झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा-2 की उपधारा-(खख) के बाद निम्नलिखित उपधारा-(खखख) जोड़ा जायेगा, यथा 2 (खखख)

“सहकारी समिति” से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अन्तर्गत निबंधित कोई संगठन।

3. अधिनियम 6, 1935 की धारा-2 की उपधारा-(ड) में संशोधन ।

झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा-2 की उपधारा-(ड) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:-

2 (ड) “बोर्ड” से अभिप्रेत है निदेशक बोर्ड अथवा शासी निकाय अथवा प्रबन्ध समिति, जिस नाम से भी उसे अभिहित किया गया हो, जिसके निदेशन एवं नियंत्रण में सहकारी समिति के कामकाज का प्रबन्ध सौंपा गया हो;

4. अधिनियम 6, 1935 की धारा-2 की उपधारा-(चच) में संशोधन । -झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा-2 की उपधारा-(चच) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:-

“बहुधंधी सहकारी सोसाइटी” से अभिप्रेत है, वह प्राथमिक सोसाइटी, जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों को विविध प्रकार की सेवाओं, जिसका संबंध साख (क्रेडिट), व्यवसाय, उद्योग, टिकाउ उपभोक्ता सामग्री से है, प्रदान करने के लिए किया गया हो।

5. अधिनियम 6, 1935 की धारा-2 की उपधारा-(छछ) में संशोधन - झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा-2 की उपधारा-(छछ) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:- “पदधारी” से अभिप्रेत है सहकारी समिति के सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव अथवा कोषाध्यक्ष तथा किसी सहकारी समिति के बोर्ड में निर्वाचित कोई व्यक्ति ।

6. अधिनियम 6, 1935 की धारा-2 की उपधारा-(छछछ) में संशोधन - झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा-2 की उपधारा-(छछछ) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:-

"प्राथमिक सोसाइटी" से अभिप्रेत है, वैसी निबंधित सोसाइटी, जिसका सदस्य सिर्फ व्यक्ति अथवा स्वयं सहायता समूह हो।

7. अधिनियम 6, 1935 की धारा-2 की उपधारा-(छछछछ) में संशोधन - झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा-2 की उपधारा-(छछछछ) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:-

"प्राथमिक कृषि साख (क्रेडिट) सोसाइटी" से अभिप्रेत है, ऐसी सोसाइटी, जिसका प्राथमिक उद्देश्य या मूल कर्तव्य अपने सदस्यों को कृषि अथवा कृषि से संबंधित प्रयोजन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना (फसलों का विपणन एवं बहुधंधी सहकारी सोसाइटी भी शामिल है)

8. अधिनियम 6, 1935 की धारा-2 की उपधारा-(ण) में संशोधन - झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा-2 की उपधारा-(ण) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:-

"केन्द्रीय समिति" से अभिप्रेत है, ऐसी सहकारी समिति, जो कि 'फेडरेशन' एवं 'यूनियन' से भिन्न हो तथा ऐसी समिति, जिसके सदस्य कोई अन्य सहकारी समिति हो तथा उपविधियाँ में यदि प्रावधान हो तो, कोई व्यक्ति भी सदस्य हो सकता है।

9. अधिनियम 6, 1935 की धारा-2 की उपधारा-(ण) के बाद अन्तःस्थापन। - झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा-2 की उपधारा-(ण) के बाद निम्नलिखित उपधारा-(प) जोड़ा जायेगा, यथा 2 (प) "सामान्य निकाय" से अभिप्रेत है उस सहकारी समिति के सम्मिलित रूप से सभी सदस्य अथवा सभी सदस्यों के प्रतिनिधि।

10. अधिनियम 6, 1935 की धारा-2 की उपधारा-(प) के बाद अन्तःस्थापन। - झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा-2 की उपधारा-(प) के बाद उपधारा (फ) जोड़ा जायेगा, यथा: "प्राधिकृत व्यक्ति" से अभिप्रेत है झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम-1935 की धारा-45(1) में इसी रूप में निदेशित व्यक्ति।

11. अधिनियम 6, 1935 की धारा-2 की उपधारा-(फ) के बाद अन्तःस्थापन। - झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा-2 की उपधारा-(फ) के बाद उपधारा (ब) जोड़ा जायेगा, यथा: "राज्य स्तरीय सहकारी समिति" से अभिप्रेत है, ऐसी सहकारी समिति जिसका कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण राज्य में विस्तारित हो और झारखण्ड सहकारी अधिनियम-1935 में इस रूप में परिभाषित किया गया हो।

12. अधिनियम 6, 1935 की धारा-2 की उपधारा-(ब) के बाद अन्तःस्थापन। - झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा-2 की उपधारा-(ब) के बाद उपधारा (भ) जोड़ा जायेगा, यथा "क्रियाशील निदेशक" से अभिप्रेत है नियमावली अथवा सहकारी समिति के उपविधियों में विनिर्दिष्ट समिति के क्रियाशील कार्यपालक निदेशक।

13. अधिनियम 6, 1935 की धारा-13 (क) की उपधारा-(1) एवं (2) में संशोधन । - झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा-13 (क) की उपधारा-(1) एवं (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:-

- (1) राज्य सरकार का यह दायित्व होगा कि वह राज्य में सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्यकलाप, जनतांत्रिक सदस्य नियंत्रण, सदस्य आर्थिक हिस्सेदारी एवं व्यावसायिक प्रबन्धन को प्रोत्साहित करे एवं उसका उन्नयन करे और इस ओर ऐसे कदम उठाये जिनकी आवश्यकता हो;

(2) उपधारा-(1) के प्रावधानों के तहत सहकारी समिति के प्रोत्साहन एवं उन्नयन हेतु राज्य सरकार यदि आवश्यक समझे तो:-

- (क) किसी सामान्य या विशेष श्रेणी की सहकारी समिति के विकास में सहायता के लिए सहकारी समिति की हिस्सा पूँजी में अंशदान दे सकेगी;
- (ख) किसी सहकारी समिति की हिस्सा पूँजी के निर्माण एवं सम्बर्द्धन के लिए सहायता कर सकेगी;
- (ग) सहकारी समिति को ऋण या अग्रिम दे सकेगी या सहकारी समिति के द्वारा निर्गत ऋण-पत्र पर मूल के पुर्नभुगतान और सूद के भुगतान की गारंटी ले सकेगी या किसी सहकारी समिति को दिये गये ऋण या अग्रिम के मूल के पुर्नभुगतान और सूद के भुगतान की गारंटी ले सकेगी।

14. अधिनियम 6, 1935 की धारा 14 की उपधारा (2) में संशोधन - झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 14 की उपधारा (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथा: इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सहकारी समिति नियमावली/उपविधियों और इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप निमित्त प्रबंध समिति में निबंधित समिति का प्रबंधन होगा।

इस अधिनियम के किसी प्रावधान अथवा इसके अधीन बनाई गई नियमावली अथवा किसी सहकारी समिति के उपविधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सहकारी समिति के निदेशकों/बोर्ड की अधिकतम संख्या-21 (इक्कीस) से अधिक नहीं होगी।

परन्तु और भी कि प्रत्येक सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी समिति में 50 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। उस 50 प्रतिशत आरक्षित स्थान में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए दो स्थान वैसी समितियों में आरक्षित होंगे, जिन समितियों में उक्त वर्ग या कोटि से सदस्य होंगे। इस प्रकार से आरक्षित स्थान अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला का पद निर्वाचन या/और सहयोजन द्वारा भरे जायेंगे।

इस अधिनियम के प्रावधान सभी समितियों यथा: प्राथमिक से शीर्ष सहकारी समितियों तक लागू किया जायेगा।

परन्तु और कि प्राथमिक समिति तथा शीर्ष समिति तक ऐसे आरक्षण की व्यवस्था इस उद्देश्य हेतु इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमावली द्वारा परिचालित होंगे।

15. अधिनियम 6, 1935 की धारा 14 की उपधारा (4) का पुर्नसंख्याकन। - झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 14 की उपधारा 4 उपधारा 4(I) के रूप में पुर्नसंख्यांकित की जायेगी।

16. अधिनियम 6, 1935 की धारा-14 की उपधारा-(4) के बाद उपधारा- (4 ख) का अन्तःस्थापन। - झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा-14 की उपधारा-(4)के बाद उपधारा- (4 ख) निम्नलिखित रूप से जोड़ी जायेगी:-

इस अधिनियम के किसी प्रावधान अथवा इसके अधीन बनायी गयी नियमावली अथवा किसी सहकारी समिति की उपविधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी समिति के बोर्ड में बैंकिंग, प्रबन्धन, वित्त अथवा समिति के उद्देश्यों और कार्यकलाप के अनुरूप दूसरे क्षेत्रों के विशिष्ट योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को सदस्य के रूप में समिति द्वारा सहयोजित किया जायेगा

परन्तु इस प्रकार सहयोजित सदस्यों की संख्या दो से अधिक नहीं होगी और ये उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट बोर्ड के अधिकतम संख्या से अतिरिक्त होगा

परन्तु और कि ऐसे सहयोजित सदस्यों को सहकारी समिति के किसी निर्वाचन में ऐसी सदस्यता के तहत मत देने का अधिकार नहीं होगा और न वे बोर्ड में पदधारी के रूप में निर्वाचित हो सकेंगे

परन्तु और कि सहकारी समिति के क्रियाशील निदेशक भी बोर्ड के सदस्य होंगे और ऐसे सदस्यों की गणना उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट बोर्ड के अधिकतम संख्या में नहीं की जायेगी।

17. अधिनियम 6, 1935 की धारा-14 की उपधारा-(9) में संशोधन । - झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा-14 की उपधारा-(9) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:-

इस अधिनियम के किसी प्रावधान अथवा इसके अधीन बनाई गई नियमावली अथवा किसी सहकारी समिति की उपविधियों में किसी बात के अन्तर्विष्ट होने पर भी, बोर्ड का चुनाव बहिर्गामी बोर्ड के पदावधि समाप्ति तिथि से पूर्व किया जायेगा, ताकि नये बोर्ड बहिर्गामी बोर्ड के पदावधि समाप्ति के उपरांत पदभार ग्रहण कर सके।

सहकारी समिति का अधीक्षण, निदेशन और मतदाता सूची को तैयार कराने का संचालन, मतदान कराना आदि जिम्मेवारी इस अधिनियम, नियमावली या उपविधियों द्वारा विनिर्दिष्ट व्यक्ति/ अथॉरिटी में सन्निहित होगी।

इस अधिनियम के किसी प्रावधान अथवा इसके अधीन बनाई गई नियमावली अथवा किसी सहकारी समिति के नियमों या उपविधियों में किसी बात के अन्तर्विष्ट होने पर भी, किसी सहकारी समिति की बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों एवं पदाधिकारियों की पदावधि निर्वाचन की तिथि से पाँच वर्षों की होगी और पदाधिकारियों की पदावधि बोर्ड के पदावधि का सह-अन्तक होगा।

परन्तु कि बोर्ड में किसी कारणवश हुई रिक्ति को बोर्ड द्वारा उन्ही वर्ग के सदस्यों से मनोनयन द्वारा भरा जायेगा, जिनसे संबंधित आकस्मिक रिक्ति उत्पन्न हुई हो, यदि बोर्ड के मूल पदावधि से आधे से कम की पदावधि बाकी हो।

परन्तु और कि किसी सहकारी समिति के निर्वाचित बोर्ड में यदि मूल पदावधि से आधे से अधिक की पदावधि बाकी हो, और बोर्ड में किसी कारणवश निर्वाचित सदस्यों एवं पदाधिकारियों का पद रिक्त हो जाय, तो शेष अवधि के लिए सहकारी समिति द्वारा विशेष आम सभा द्वारा उपनिर्वाचन से रिक्ति को भरा जायेगा।

18. अधिनियम 6, 1935 की धारा-14 की उपधारा-(10) में संशोधन । - झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा-14 की उपधारा-(10) निरस्त की जाएगी।

19. अधिनियम 6, 1935 की धारा-27 में संशोधन। - झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा-27 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:-

(1) सहकारी समिति का कोई भी सदस्य नियमों या समिति की उपविधि में विहित सदस्यता विषयक अदायगी कर देने के बाद समिति के सदस्य के अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे

परन्तु यह कि इस अधिनियम के किसी प्रावधान में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुये भी किसी सहकारी समिति का सदस्य नियमावली अथवा उपविधियों में विहित सहकारी समिति के प्रबंधन में सहभागिता हेतु बुलाई गई बैठकों में आवश्यकता के अनुरूप न्यूनतम उपस्थिति तथा समिति द्वारा प्रदत्त सेवाओं के न्यूनतम स्तर तक उपयोग के बाद ही सदस्य के अधिकारों का प्रयोग करेंगे।

- (2) प्रत्येक सहकारी समिति अपने प्रत्येक सदस्यों के लिए उनसे संबंधित अभिलेखों, सूचनाओं तथा व्यवसाय से संबंधित नियमित संव्यवहारों के लेखाओं के संबंध में सभी जानकारी/कागजात सुगम करायेगी।
- (3) सहकारी समिति के प्रत्येक सदस्य को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह सहकारी समिति में संधारित अभिलेखों, सूचनाओं तथा व्यवसाय से संबंधित नियमित संव्यवहारों के लेखाओं के संबंध में सभी जानकारी/कागजात प्राप्त कर सकेंगे। सहकारी समिति के मुख्य कार्यपालक/ प्रबंधक सदस्य को सभी वांछित जानकारी/कागजात सुगम करायेंगे।
- (4) सहकारी समिति के सदस्यों को इस अधिनियम, इसके अधीन बनी नियमावली तथा उपविधियों में विहित प्रावधानों के तहत सहकारी शिक्षा तथा सहकारिता संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार एवं दायित्व होगा।

20. अधिनियम 6, 1935 की अध्याय-4 के बाद अध्याय-4 (क) का अन्तःस्थापन:-झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 के अध्याय-4 के बाद अध्याय-4 (क) जोड़ी जायेगी यथा:-

सहकारी समिति की वार्षिक आम सभा तथा वार्षिक विवरणियाँ

32.(क) वार्षिक आम सभा:-

(1) प्रत्येक सहकारी समिति का बोर्ड वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद छह माह के भीतर वार्षिक आम सभा बुलायेगी, जिसमें बोर्ड के सदस्यों एवं उसके पदाधिकारियों के निर्वाचन को छोड़कर, अधोलिखित सभी अथवा किसी विषय वस्तु पर विचार से किया जायेगा:-

- (क) निबन्धक के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बोर्ड द्वारा वार्षिक विवरणियों पर विचार
- (ख) बोर्ड द्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार
- (ग) सांविधिक अंकेषकों एवं आन्तरिक अंकेषकों की नियुक्ति एवं हटाया जाना
- (घ) अंकेक्षण का रिपोर्ट और निबन्धक को दाखिल किये जाने के लिए अंकेक्षित विवरण पर विचार
- (ङ) अंकेक्षण/विशेष अंकेक्षण के अनुपालन प्रतिवेदन पर विचार
- (च) धारा-39 के अधीन जाँच प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन यदि कोई हो
- (छ) शुद्ध अधिवेश का निपटान
- (ज) संचालन घाटा, यदि कोई हो, का पुनर्विलोकन
- (झ) दीर्घकालीन महत्व की योजना और वार्षिक परिचालन योजना का अनुमोदन
- (ञ) वार्षिक बजट का अनुमोदन
- (ट) विनिर्दिष्ट आरक्षित निधि एवं अन्य निधियों का सृजन
- (ठ) आरक्षित एवं अन्य निधियों की वास्तविक उपयोगिता का पुनर्विलोकन
- (ड) अन्य सहकारी समितियों में सहकारी समिति की सदस्यता के संबंध में प्रतिवेदन;
- (ढ) सदस्यता के लिए जिस व्यक्ति का आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया हो अथवा जिसकी सदस्यता बोर्ड द्वारा समाप्त कर दी गई हो, उसकी अपील
- (ण) किसी निदेशक, अंकेक्षक या आन्तरिक अंकेक्षक को उस हैसियत से अपने कर्तव्य के लिए अथवा संबंधित बैठकों में उसकी उपस्थिति के लिए देय पारिश्रमिक
- (त) संघ/परिसंघ में सहकारी समिति की सदस्यता
- (थ) अन्य संगठनों के साथ सहयोग
- (द) उपविधियों का संशोधन

- (ध) निदेशकों एवं पदधारियों के लिए आचार संहिता बनाना
- (न) सदस्यों को सम्मिलित किये जाने एवं सदस्यता समाप्त किये जाने संबंधी टिप्पणी
- (प) सहकारी समिति का विघटन
- (फ) ऐसे अन्य कृत्य, जो उपविधियाँ में विनिर्दिष्ट हों।
- (2) उपधारा (1) के प्रावधानों के तहत उपधारा (2) में विहित कार्यों के लिए सहकारी समिति की वार्षिक आम सभा उपविधियों के अनुसार अधिसूचित समय, तिथि तथा स्थान पर होगी और यदि गणपूत्रि (कोरम) हो जायेगी तो सभा का सभापतित्व सहकारी समिति के अध्यक्ष करेंगे
- परन्तु कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अथवा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में सदस्यों के द्वारा उन्ही में से निर्वाचित कोई व्यक्ति सभा का सभापतित्व करेंगे
- परन्तु और कि यदि किसी समिति का बोर्ड इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अवक्रमित हो गयी हो, तो वहाँ प्रशासक आम सभा का सभापतित्व करेंगे और उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा नाम निर्देशित कोई व्यक्ति सभा का सभापति होंगे।
- (3) आम सभा का सभापतित्व करने वाले व्यक्ति सभा की कार्यवाही का संचालन इस प्रकार करेंगे कि कारबार का निस्तार शीघ्रातिशीघ्र तथा संतोषजनक होंगे और वे सभा में व्यवस्था संबंधी सभी बिन्दुओं पर निर्णय लेंगे।
- (4) आम सभा की सूचना निर्गत होने की तिथि को समिति की जो कुल सदस्य संख्या होगी उसका पंचमांश आम सभा के लिए गणपूत्रि (कोरम) होगा।
- (5) यदि आम सभा के लिए निर्धारित समय से एक घंटा के भीतर गणपूत्रि न हो सके तो सभा ऐसी तिथि तक के लिए स्थगित कर दी जायेगी जो सात दिन से पूर्व और इक्कीस दिन के बाद नहीं होगी।
- (6) स्थगित आम सभा के लिए किसी गणपूत्रि की आवश्यकता नहीं होगी।
- (7) आम सभा में सभी प्रश्नों का निर्णय बहुमत से किया जायेगा और मतों की समता की स्थिति में सभा के सभापति निर्णायक मत देंगे।
- (8) परोक्षी मत स्वीकृत नहीं किया जायेगा, किन्तु किसी विशिष्ट सहकारी समिति अथवा सहकारी समिति के वर्ग के मामले में निबन्धक ऐसा करने की अनुमति दे सकेंगे।
- (9) आम सभा में हाथ उठाकर मतदान किया जायेगा और केवल आपवादिक मामले में, यदि निबन्धक स्वेच्छा अथवा संबंधित समिति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर निदेश दे तो, मतपत्रों के माध्यम से मतदान किया जायेगा।
- (10) आम सभा की कार्यवाहियों का वृत्त उसी प्रयोजन के लिए रखी गई एक वही में अभिलिखित किया जायेगा और सभा का सभापतित्व करने वाले व्यक्ति उस वृत्त पर हस्ताक्षर करेंगे।
- (11) आम सभा में अपनायी गई प्रक्रिया संबंधी किसी आपत्ति की अपील निबन्धक के पास की जायेगी और उस पर उनका निर्णय अंतिम होगा।
- (32) (ख) वार्षिक विवरणियाँ दाखिल करना** - प्रत्येक सहकारी समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह के भीतर निबन्धक के समक्ष वार्षिक विवरणियाँ दाखिल करेगी जिसमें निम्नलिखित विषयवस्तु सन्निहित रहेंगे:-
- (क) कार्यकलाप की वार्षिक रिपोर्ट,
- (ख) लेखाओं का अंकेक्षित विवरण,
- (ग) सामान्य निकाय द्वारा यथानुमोदित अधिवेश निपटाव हेतु योजना,

- (घ) सहकारी समिति की उपविधियों में किये गये संशोधनों की सूची, यदि कोई हो,
- (ङ) सामान्य निकाय की सभा के आयोजन की तारीख तथा निर्वाचन का संचालन जब देय हो, से संबंधित घोषणा, तथा
- (च) निबन्धक द्वारा संसूचित अधिनियम के किसी प्रावधानों के पालन हेतु आवश्यक, कोई अन्य सूचना।

21. **अधिनियम 6, 1935 की धारा-33 में संशोधन।** - झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा-33 निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित की जायेगी:-

अंकेक्षण:-

- (1) सहकारी समिति अपने लेखाओं का अंकेक्षण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार इस हेतु राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा अनुमोदित नामावली के अंकेक्षक द्वारा कराएगी। ऐसा अंकेक्षक चाटर्ड एकाउन्टेन्ट अधिनियम, 1949 के अर्थान्तर्गत या तो चाटर्ड एकाउन्टेन्ट होगा या निबन्धक के कार्यालय का अंकेक्षक होगा।
- (2) राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा अनुमोदित नामावली के अंकेक्षक अथवा चाटर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म की न्यूनतम अर्हता एवं अनुभव का निर्धारण समय-समय पर किया जाएगा। केवल ऐसे अंकेक्षक अथवा चाटर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म ही सहकारी समिति के लेखाओं का अंकेक्षण करने हेतु योग्य होंगे।
- (3) प्रत्येक सहकारी समिति के लेखाओं का अंकेक्षण सहकारी समिति के सामान्य निकाय द्वारा नियुक्त उपधारा (2) में सन्दर्भित अंकेक्षक अथवा चाटर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म द्वारा की जायेगी।
- (4) प्रत्येक सहकारी समिति के लेखाओं का अंकेक्षण वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह के भीतर करना अनिवार्य होगा, जिस वित्तीय वर्ष से ऐसा लेखा संबंधित हो।
- (5) शीर्ष सहकारी समिति के द्वारा अपने लेखाओं के अंकेक्षण के उपरान्त अंकेक्षक का प्रतिवेदन समिति के सामान्य निकाय के अनुमोदनोपरान्त तीस दिनों के भीतर निबन्धक को अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जायेगा ताकि उक्त रिपोर्ट को राज्य सरकार के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा विहित की गई प्रक्रिया के तहत विधान मण्डल के पटल पर रखा जा सके।
- (6) यह सुनिश्चित करना सहकारी समिति के बोर्ड का कर्तव्य होगा कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पैंतालीस दिनों के भीतर वार्षिक वित्तीय विवरणी को तैयार करके अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत कर दिया जाय।
- (7) अंकेक्षक के पारिश्रमिक का निर्धारण सहकारी समिति के सामान्य निकाय द्वारा किया जायेगा, जो निबन्धक द्वारा निर्धारित अंकेक्षण शुल्क के आधार पर होगा।

परन्तु यदि अंकेक्षण, निबन्धक के कार्यालय के अंकेक्षक द्वारा किया जाता है तो निबन्धक द्वारा निर्धारित अंकेक्षण शुल्क का भुगतान सहकारी समिति द्वारा किया जायेगा।

- (8) किसी सहकारी समिति के अंकेक्षक की मांग पर, सहकारी समिति के वर्तमान या पूर्व पदधारी, बोर्ड के सदस्य, सदस्य या कर्मचारी:-
- (क) ऐसी सूचना और ऐसा स्पष्टीकरण देंगे, जैसा कि आवश्यक समझा जाय, तथा
- (ख) सहकारी समिति के प्रत्येक ऐसे अभिलेखों, दस्तावेजों, बहियों, लेखाओं और भाउचरों को देखने देंगे, जो अंकेक्षक की राय में जाँच करने और प्रतिवेदन तैयार करने में उसे समर्थ होने के लिए आवश्यक हो।

(9) जहाँ कोई सहकारी समिति समय पर अपने वार्षिक लेखाओं का अंकेक्षण कराने में असफल हो, वहाँ के लिए नियत तारीख से नब्बे दिनों के भीतर निबन्धक, सहकारी समिति के लेखाओं का अंकेक्षण करायेंगे।

(10) अंकेक्षण करने का खर्च सहकारी समिति द्वारा वहन किया जायेगा।

22. अधिनियम 6, 1935 की धारा-33 के बाद 33 (क) का अन्तःस्थापन। - झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा-33 के बाद धारा-33 (क) निम्नलिखित रूप में जोड़ी जायेगी:-

33.(क) विशेष अंकेक्षण:-

(1) राज्य सरकार या अन्य सहकारी समिति या अन्य संस्थाओं या अन्य वाह्य व्यक्ति से निधियों का संव्यवहार करने वाले किसी सहकारी समिति का विशेष अंकेक्षण ऐसे ऋणदाताओं के अनुरोध पर या स्वेच्छा से निबन्धक द्वारा, ऐसे विनिर्दिष्ट आदेश/निर्देश के तहत जैसा कि निबन्धक द्वारा कारणों सहित अभिलिखित किया जाय, शुरू की जा सकेगी।

(2) उपधारा- (1) के अधीन विशेष अंकेक्षण निबन्धक के अधीन पदस्थापित जिला अंकेक्षण पदाधिकारी/वरीय स्तर के अंकेक्षण पदाधिकारी या ऐसे पदाधिकारियों की गठित कमिटी द्वारा किया जायेगा।

(3) जहाँ विशेष अंकेक्षण में गम्भीर कुप्रबन्ध का पता चले, वहाँ ऐसे विशेष अंकेक्षण का शुल्क, जो ऐसे विशेष अंकेक्षण के लिए निबन्धक द्वारा विनिर्धारित हो, सहकारी समिति से या कुप्रबन्ध के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूल किया जा सकेगा।

(4) प्रत्येक विशेष अंकेक्षण निबन्धक द्वारा आदेश निर्गत की तारीख से एक सौ बीस दिनों के भीतर पूरी करके रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(5) ऐसे विशेष अंकेक्षण रिपोर्ट में निम्नलिखित विवरण अन्तर्विष्ट रहेगा:-

(क) प्रत्येक संव्यवहार जो अंकेक्षक को अधिनियम, अथवा अधिनियम के अधीन बनी नियमावली अथवा सहकारी समिति की उपविधियों के प्रतिकूल प्रतीत हो,

(ख) किसी घाटा अथवा क्षति की राशि जो किसी व्यक्ति की आपराधिक उपेक्षा अथवा कदाचार के कारण उपगत हुई प्रतीत हो,

(ग) वैसी कोई धनराशि जो किसी व्यक्ति को लेखा-जोखा में लानी चाहिये थी किन्तु नहीं लाई गई, एवं

(घ) सहकारी समिति का कोई धन अथवा सम्पत्ति जिसे सहकारी समिति के संगठन अथवा प्रबंध में भाग लेने वाला किसी व्यक्ति अथवा सहकारी समिति के किसी भूतपूर्व अथवा वर्तमान सदस्य अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने दुर्विनियोग किया है अथवा छल से रख लिया है।

(6) विशेष अंकेक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर निबन्धक इसकी प्रतियाँ:-

(क) आवेदक ऋणदाता

(ख) सम्बन्धित सहकारी समिति, और

(ग) जहाँ आवश्यक हो, वहाँ धारा-40 के तहत अधिशुल्क की कार्यवाही का प्रस्ताव दाखिल करने हेतु अधिकृत अंकेक्षण पदाधिकारी को सम्प्रेषित करेंगे।

23. अधिनियम 6, 1935 की धारा-33 (क) के बाद धारा-33 (ख) का अन्तःस्थापन। - झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा-33 (क) के बाद धारा-33 (ख) निम्नलिखित रूप में जोड़ी जायेगी:-

33.(ख) लेखाओं तथा अभिलेखों का संधारण:-

- (1) प्रत्येक सहकारी समिति अपने निबंधित कार्यालय में निम्नलिखित लेखाओं और अभिलेखों को रखेगी:-
- (क) समय-समय पर किए गए संशोधन सहित इस अधिनियम की एक प्रति
 - (ख) कार्यवृत्त पुस्तक
 - (ग) निबंधन प्रमाण-पत्र तथा निबंधित उपविधियों की एक प्रति और संशोधन की तारीख सहित समय-समय पर निबंधित संशोधनों की एक प्रति
 - (घ) ऐसे संघ/परिसंघ जिसका यह सदस्य हो, की तथा अपने सदस्य सहकारी समिति की अभिप्रमाणित उपविधियों की एक-एक प्रति
 - (ङ.) सहकारी समिति द्वारा प्राप्त तथा खर्च की गई सभी धनराशि, उनके प्रयोजनों सहित, का लेखा
 - (च) सहकारी समिति द्वारा सामानों की सभी खरीद-बिक्री का लेखा
 - (छ) सहकारी समिति की सम्पत्तियों तथा दायित्वों का लेखा
 - (ज) कुल सदस्यता तथा विभिन्न सेवाओं का सदस्यवार उपयोग प्रदर्शित करने वाली पंजी
 - (झ) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीस दिनों के भीतर अद्यतन की गई चालू वित्त वर्ष के लिए मताधिकार प्राप्त सदस्यों की सूची
 - (ञ) बोर्ड नीतियों की प्रतियाँ
 - (ट) वार्षिक रिपोर्ट, अंकेक्षण प्रतिवेदन, विशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन, जाँच प्रतिवेदन और उनका अनुपालन
 - (ठ) अन्य विधियों तथा विनियमों की प्रतियाँ, जिनके अध्याधीन सहकारी समिति हो
 - (ड) ऐसे अन्य दस्तावेज जो सहकारी समिति के कृत्यों से सुसंगत हो, परन्तु यह कि जहाँ सहकारी समिति के शाखा-कार्यालय हैं वहाँ शाखा-कार्यालयों संबंधी लेखा एवं अभिलेख, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पचीस दिनों के अंदर किसी अवधि के लिए निबंधित कार्यालय में उपलब्ध रहेगा
 - (ढ) नावार्ड, रिजर्व बैंक तथा निबन्धक द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/प्रावधानों के तहत आवश्यक अन्य सभी दस्तावेज तथा पंजियाँ परिपत्र आदि।
- (2) समर्थकारी अभिलेखों तथा भाउचरों सहित, प्रत्येक सहकारी समिति की लेखा पुस्तकें ऐसी अवधि के लिए परिरक्षित की जायेगी, जैसी कि तत्समय प्रवृत्त किन्हीं विधियों के अध्याधीन उपविधियों में उपबंधित की जाय।

24. अधिनियम 6, 1935 की धारा 40 की उपधारा (1) में अन्तःस्थापन। - झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा 40 की उपधारा (1) के प्रथम पंक्ति में निम्नलिखित शब्द जोड़ा जायेगा:- शब्द यदि धारा 33 के अधीन अंकेक्षण के बाद शब्द तथा धारा 33 (क) के अधीन विशेष अंकेक्षण।

25. अधिनियम 6, 1935 की धारा 41 की उपधारा (1) में संशोधन। - झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा 41 की उपधारा (1) निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित की जायेगी-

41. बोर्ड का अधिक्रमण:- (1) इस अधिनियम के किसी प्रावधान अथवा इसके अधीन बनाई गई नियमावली में किसी बात के अन्तर्विष्ट होने पर भी किसी सहकारी समिति का बोर्ड छः माह से अधिक अवधि के लिए अवक्रमित नहीं रहेगा।

परन्तु यदि निबन्धक की राय में किसी सहकारी समिति का बोर्ड जिस सहकारी समिति में राज्य सरकार का उसके हिस्सा पूँजी में अंशदान हो अथवा राज्य सरकार द्वारा ऋण अथवा वित्तीय सहायता प्रदत्त की गई हो अथवा ऋण के लिए कोई गारंटी दी गई हो,

i. यदि वह समिति लगातार ऋण अदायगी में चूक की हो,

- ii. इस अधिनियम, नियमावली या उपविधियों द्वारा अधिरोपित कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही की हो,
- iii. सहकारी समिति अथवा उसके सदस्यों के हित के प्रतिकूल कार्य की हो,
- iv. बोर्ड के गठन अथवा कार्यकलाप में गतिरोध हो,
- v प्राधिकार या निकाय जैसा कि अधिनियम/नियम/नियमावली में प्रावधानित है, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप निर्वाचन के संचालन में विफल हुआ हो,

तो उस सहकारी समिति के बोर्ड को अपनी आपत्ति, यदि कोई हो, देने का अवसर प्रदान करने के पश्चात कारणों सहित लिखित आदेश द्वारा सहकारी समिति के बोर्ड को अधिकतम छः माह के लिए अधिक्रमित कर सकेंगे और आदेश दे सकेंगे कि इसके सभी अथवा कोई सदस्य आदेश में विहित कालावधि पाँच वर्ष से अनधिक तक के लिए सहकारी समिति के बोर्ड में निर्वाचन के लिए अयोग्य होंगे। निबन्धक इस धारा के अधीन पारित प्रत्येक आदेश को अभिलिखित करेंगे और निबन्धित डाक से संबंधित सहकारी समिति को सूचित करेंगे।

परन्तु कि, ऐसी सहकारी समिति के मामले में जो बैंकिंग का कारोबार कर रही हो, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 के प्रावधान भी लागू होंगे;

परन्तु और कि बैंकिंग का कारोबार करने वाली ऐसी सहकारी समिति के मामले में बोर्ड के अधिक्रमण की अवधि अधिकतम एक वर्ष की होगी।

परन्तु और कि बैंकिंग का कारोबार करने वाली सहकारी समिति के बोर्ड का अधिक्रमण रिजर्व बैंक के परामर्श से किया जायेगा।

किसी सहकारी समिति के बोर्ड के अवक्रमित होने की स्थिति में निबन्धक द्वारा नियुक्त प्रशासक समिति का निर्वाचन कराने में हर संभव सहायता प्रदान करेगा। यह व्यवस्था पूर्णतः अन्तरिम व्यवस्था होगी और प्रशासक, निर्धारित अवधि के भीतर निर्वाचन के उपरान्त नये बोर्ड को समिति का प्रबन्धन सौंप देगा।

परन्तु कि जहाँ राज्य सरकार द्वारा हिस्सापूँजी अथवा ऋण अथवा वित्तीय सहायता अथवा किसी प्रकार की गारंटी नहीं दी गई हो और जहाँ सहकारी समिति का बोर्ड कालावधि के पूर्व निर्वाचन संचालित करने में असफल रहता है, तो सहकारी समिति के निबन्धक निर्वाचन कराने हेतु एक तदर्थ बोर्ड की नियुक्ति के लिए संयुक्त रूप से सदस्यों की एक विशेष आम सभा आयोजित करने का आदेश दे सकेंगे।

परन्तु निर्वाचन कराने हेतु तदर्थ समिति में वर्हिगामी बोर्ड के सदस्य अथवा पदधारी सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।

परन्तु और कि इस प्रकार नियुक्त तदर्थ बोर्ड की अवधि छः माह से अधिक की नहीं होगी, और तदर्थ बोर्ड समिति को निर्वाचन के संचालन के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी। यह व्यवस्था पूर्णतः अन्तरिम व्यवस्था होगी और इस प्रकार नियुक्त तदर्थ बोर्ड, निर्धारित अवधि के भीतर निर्वाचन के उपरान्त नये बोर्ड को समिति का प्रबन्धन सौंप देगा।

26. अधिनियम 6, 1935 की धारा 41 की उपधारा -(2) में संशोधन । - झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा -41 की उपधारा (2) निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित की जायेगी-
- 41(2) जहाँ उपधारा- 1 के तहत कार्यवाही करते समय निबन्धक की राय में निबन्धित समिति के हित में बोर्ड का निलंबन आवश्यक हो, तो वे बोर्ड को निलम्बित कर सकेंगे, जो उसके बाद कार्य करना बन्द कर देंगी और उपधारा -1(क) की कार्यवाही के समाप्ति तक निबन्धित समिति के कार्यकलाप के प्रबन्धन के लिए ऐसी व्यवस्था करेंगे, जो वे उचित समझें।

परन्तु कि यदि इस प्रकार निलम्बित बोर्ड अधिक्रमित नहीं होती है, तो छह माह के उपरान्त कार्य करने लगेगी और निलम्बन में रहने की अवधि की गणना उसके पदावधि में की जायेगी।

27. अधिनियम 6, 1935 की धारा 41 की उपधारा (3) में संशोधन। - झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा 41 की उपधारा (3) निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित की जायेगी-

(3) जब कोई सहकारी समिति उपधारा-(1) के तहत अधिक्रमित की जायेगी तो निबन्धक सहकारी समिति के कार्य संचालन के लिए प्रशासक नियुक्त करेंगे। नियुक्त प्रशासक उपधारा-(1) के तहत विनिर्धारित अवधि के भीतर सहकारी समिति के बोर्ड के निर्वाचन हेतु सभी आवश्यक उपाय करेंगे तथा निर्वाचित बोर्ड को समिति के प्रबंध का कार्यभार सौंप देंगे।

परन्तु यह कि अधिक्रमण की अवधि में प्रशासक को बदलने की शक्ति निबन्धक में होगी।

28. अधिनियम 6, 1935 की धारा 41 की उपधारा (4) में संशोधन। - झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा 41 की उपधारा (4) निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित की जायेगी-

(4) उपधारा-(3) के तहत नियुक्त प्रशासक को सहकारी समिति के कार्य संचालन के लिए निबन्धक द्वारा ऐसा पारिश्रमिक निर्धारित किया जायेगा जो वह उचित समझें। निर्धारित पारिश्रमिक सहकारी समिति के खाते से भुगतये होगा।

परन्तु कि उपधारा-(3) के तहत नियुक्त प्रशासक, निबन्धक द्वारा निर्मित सेवा शर्तों के अध्याधीन कार्य करेंगे तथा इस अधिनियम, नियमावली एवं समिति की उपविधियों में बोर्ड को प्रदत्त सभी कर्तव्यों तथा दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

29. अधिनियम 6, 1935 की धारा 42 में संशोधन। - झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा 42 निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित की जायेगी-

42. सहकारी समिति का विघटन:- अधिसूचना जारी करके निबन्धक किसी सहकारी समिति को विघटित करने का आदेश दे सकेंगे यदि:-

- (क) कोई सहकारी समिति अपने विद्यमान कुल सदस्यों की संख्या के तीन-चैथाई सदस्यों की सहमति से पारित विशेष संकल्प द्वारा समिति के विघटन हेतु अनुरोध करें;
- (ख) धारा-35 के अधीन जाँच अथवा धारा-34, धारा-36 अथवा धारा-37 के अधीन निरीक्षण के बाद यदि निबन्धक का ऐसा मत हो कि सदस्यों के हित में उस सहकारी समिति का विघटन आवश्यक है;
- (ग) निबन्धन के उपरान्त सहकारी समिति द्वारा कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया है अथवा कार्य करना बन्द कर दिया गया है;
- (घ) निबन्धन की शर्तों के प्रतिकूल सहकारी समिति के सदस्यों की संख्या कम होकर दस से कम हो गई हो;

परन्तु ऐसा आदेश सहकारी समिति के हिस्साधारक सदस्यों तथा हितबद्ध व्यक्तियों/संस्थाओं को कम से कम एक माह का नोटिस देकर उन्हें सुनने के पश्चात् ही पारित किया जायेगा।

30. अधिनियम 6, 1935 की धारा 43 की उपधारा (1) में संशोधन। - झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा 43 की उपधारा (1) निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित की जायेगी-

43 (1) विघटन आदेश के विरुद्ध अपील:- उस सहकारी समिति का कोई सदस्य अथवा हितबद्ध व्यक्ति/संस्था शासकीय राजपत्र में उस आदेश के प्रकाशित होने की तिथि से दो माह के भीतर उस आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार के समक्ष अपील कर सकेगा।

31. अधिनियम 6, 1935 की धारा- 44 क-ट. में संशोधन। -झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा- 44 क-ट. निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:-

विभाजन, समामेलन, संविलियन, समझौता आदि:- (1) किसी सहकारी बैंक के बारे में समझौता या व्यवस्था या उसके समामेलन या संविलियन या पुनर्निर्माण अथवा उसकी आस्तियों और दायित्वों के विभाजन या अंतरण की कोई स्कीम मंजूर करने के आदेश, रिजर्व बैंक की पूर्वलिखित मंजूरी के बिना न दिया जाएगा।

(2) जहाँ केन्द्रीय सरकार ने किसी सहकारिता बैंक के संबंध में, बैंकारी विनियमन अधिनियम (बैंकिंग रेगुलेशन्स ऐक्ट), 1949 (10, 1949) की धारा 45 की उप-धारा (2) की अधीन अधिस्थगन-आदेश दिया हो, वहाँ निबंधक रिजर्व बैंक के पूर्वलिखित अनुमोदन से अधिस्थगन की अवधि में निम्नलिखित स्कीम तैयार कर सकेगा:-

- (i) सहकारिता बैंक के पुनर्निर्माण के लिए, या
- (ii) सहकारी बैंक का संविलियन
- (iii) किसी अन्य सहकारिता बैंक (इसमें आगे "अंतरिती/संविलित बैंक" के रूप में निर्दिष्ट) के साथ उसके समामेलन के लिए।

(3) इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी, यदि कोई सहकारिता बैंक, जो निक्षेप-बीमा निगम अधिनियम (डिपोजिट इन्श्योरेंस कॉर्पोरेशन ऐक्ट) 1961 (47,1961) के अर्थ के अन्तर्गत बीमाकृत बैंक हो, समामेलित किया जाय या संविलित या जिसके संबंध में समझौता या व्यवस्था अथवा पुनर्निर्माण की कोई स्कीम मंजूर की गयी हो और निक्षेप-बीमा निगम, उस अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (2) के अधीन बीमाकृत बैंक के निक्षेपकर्ताओं को भुगतान करने का भागी हो गया हो, तो ऐसा बीमाकृत बैंक जिस बैंक के साथ समामेकित किया गया हो वह बैंक या संविलित अथवा ऐसे समामेलन या संविलित के बाद गठित नया सहकारिता बैंक अथवा, यथास्थिति, बीमाकृत या अंतरिती/संविलित बैंक, उस अधिनियम की धारा 21 में निर्दिष्ट परिस्थितियों में, सीमा तक और रीति से, निक्षेप बीमा निगम को प्रतिसंदत्त करने की मध्यता के अधीन होगा।

32. अधिनियम 6, 1935 की धारा- 44 क-ड.में संशोधन। -झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा- 44 क-ड. निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:-

निक्षेप बीमा निगम का प्रतिदान (वापसी):- जहाँ कोई सहकारी बैंक निक्षेप बीमा निगम अधिनियम, 1961 (47,1961) के अर्थ के अन्तर्गत बीमाकृत बैंक होने के नाते परिसमाप्त हो जाय या समापनाधीन कर लिया जाय और निक्षेप बीमा निगम उस अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (1) के अधीन परिसमापक वैधानिक रूप से बीमाकृत बैंक के निक्षेपकर्ताओं को भुगतान (रकम वापसी) करने की दायी हो जाए तो, निक्षेप बीमा निगम को उस अधिनियम की धारा 21 में उपबंधित सीमा तक और रीति से प्रतिदान (रकम वापसी) की जाएगी।

33. अधिनियम 6, 1935 की धारा 44 की उपधारा (क-प), में संशोधन - झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा 44 की उपधारा (क-प) निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित की जायेगी-

अध्याय 10-ग का अध्यारोही प्रभाव इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनायी गयी नियमावली या निबंधित समिति की उपविधियाँ या किसी अध्याय के उपबंध के अन्तर्गत निर्गत कोई आदेश में किसी प्रतिकूल या असंगत बात होने पर भी इस अध्याय के प्रावधानों का अध्यारोही प्रभाव होगा।

34. अधिनियम 6, 1935 की धारा 44 की उपधारा (क-फ) में संशोधन - झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा 44 की उपधारा (क-फ) 21 निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित की जायेगी-

कैडर प्रणाली को समाप्त करना- अल्पकालीन साख संरचना अन्तर्गत किसी सहकारी समिति में कार्मिकों की सामान्य कैडर प्रणाली नहीं रहेगी तथा कैडर प्रणाली तुरन्त समाप्त हो जाएगी।

35. अधिनियम 6, 1935 की धारा 45 की उपधारा (1), धारा 45 (1) (क), धारा 45 (1) (ख) में संशोधन। - झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा 45 की उपधारा (1), धारा 45 (क), धारा 45 (ख) निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित की जायेगी-

45. अपराध और दण्ड-(1) इस अधिनियम के अधीन अपराध होगा यदि-

- (क) एक सहकारी समिति अथवा सहकारी समिति का कोई पदाधिकारी अथवा सदस्य जानबूझकर मिथ्या विवरणी बनाये या मिथ्या सूचना दे अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति अथवा निबन्धक को उनके द्वारा अपेक्षा किये जाने पर जानबूझकर कोई सूचना नहीं दें, अथवा
- (ख) कोई व्यक्ति जानबूझकर अथवा बिना किसी युक्तिसंगत सफाई के किसी सम्मन, अधियाचना अथवा इस अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के तहत निर्गत, विधिसम्मत लिखित आदेश की अवज्ञा करें, अथवा
- (ग) कोई नियोक्ता बिना किसी पर्याप्त कारण के अपने कार्मिकों से कटौती की गई राशि को कटौती की तिथि से चौदह दिनों के भीतर एक सहकारी समिति को भुगतान करने में असफल हो, अथवा
- (घ) कोई सहकारी समिति का कोई पदाधिकारी अथवा अभिरक्षक अपने अभिरक्षा में रखनेवाली सहकारी समिति के पंजियों, लेखाओं, दस्तावेजों, अभिलेखों, नकद, प्रतिभूति एवं अन्य परिसम्पत्तियों का प्रभार अधिकृत व्यक्ति को सौंपने में असफल हो, अथवा
- (ङ) कोई भी व्यक्ति सहकारी समिति के बोर्ड के सदस्यों अथवा पदधारियों के निर्वाचन के पूर्व, निर्वाचन के दौरान अथवा पश्चात् भ्रष्ट आचरण अपनाया हो।

(2) इस धारा के उपधारा-(1) के अधीन किया गया कोई अपराध एक वर्ष तक की अवधि के कारावास से या 2000/- (दो हजार) रु० तक के जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा;

परन्तु यह कि जहाँ कोई व्यक्ति दुर्विनियोजन, कपट, न्यास-भंग, छल या ऐसे अन्य किसी कार्य जिसमें नैतिक अक्षमता अन्तर्गस्त हो, का दोषी हो, जिसके परिणामस्वरूप सहकारी समिति को हानि हुई हो, तो वह भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के सुसंगत उपबन्धों के अधीन भी दण्डनीय होगा।

36. अधिनियम 6, 1935 की धारा 47 की उपधारा (2) में संशोधन। - झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा 47 की उपधारा (2) निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित की जायेगी-

(2) इस अधिनियम की धारा-48 की उपधारा (1) (ग) के अधीन अपराध को छोड़कर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (2, 1974) के प्रयोजनार्थ इस अधिनियम का प्रत्येक अपराध संज्ञेय माना जाएगा।

37. अधिनियम 6, 1935 की धारा 66 (ख) की उपधारा (1) में संशोधन। - झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा 66 की उपधारा (1) निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित की जायेगी-

66. (ख)(1)सहकारी समितियों की कार्मिक नीति:- सहकारी समितियों को अपनी उपविधियों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार समिति के कार्मिकों के पदों के स्वरूप और संख्या तथा कार्मिकों की भर्ती की रीति अवधारित करने की स्वायत्तता होगी। इसके लिए सहकारी समिति अपनी कार्मिक नीति बना सकेगी। सहकारी समितियाँ अपनी उपविधियों के प्रावधानों एवं कार्मिक नीति के तहत अन्य के अलावे निम्नलिखित को विहित कर सकेगी:-

- (1) अर्हता, आयु और अनुभव,
 - (2) वेतनमान और अन्य उपलब्धियाँ,
 - (3) भर्ती की रीति,
 - (4) सेवा की शर्तें, और
 - (5) अपनाई जानेवाली अनुशासनिक प्रक्रिया।
38. अधिनियम 6, 1935 की धारा 66 (ख) की उपधारा (2) में संशोधन। -झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा 66 की उपधारा (2) निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित की जायेगी-
- (2) उपविधियों के प्रावधानों एवं कार्मिक नीति का उल्लंघन कर की गई नियुक्ति अवैध समझी जायेगी, मानों ऐसी नियुक्ति कभी नहीं की गई थी एवं वेतन तथा अन्य भत्तों के रूप में किये गये भुगतान की राशि धारा 40 के अन्तर्गत वसूलनीय होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से
बी० बी० मंगलमूर्ति,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची

विधि (विधान) विभाग

-अधिसूचना

23 नवम्बर, 2015

संख्या-एल०जी०-27/2015-141--लेज० झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक-07/11/2015 को अनुमत झारखण्ड सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2015 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

The Jharkhand Co-operative Societies (Amendment) Act, 2015 **(Jharkhand Act 21, 2015)**

An Act to amend the Jharkhand Co-operative Societies Act, 1935

Preamble:

Whereas voluntarily constituted Co-operative societies can lead to the socio-economic betterment of their members based on their participation, democratic control and autonomous functioning so as to act more meaningfully in the interests of their members;

And where as it is the obligation of the state government to promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control and professional management of the Co-operative societies in the State and promote them and take such measures as are necessary for this purpose;

And where as in pursuance of the 97th amendment Act of the constitution of India, many amendments are imperative in the Jharkhand Co-operative societies Act, 1935

Be it enacted by the Governor of Jharkhand in the 66th year of the Republic of India as follows: -

1. Short title, extent and commencement –

- (1) This Act may be called the Jharkhand Co-operative Societies (amendment) Act, 2015.
- (2) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.
- (3) It shall come into force at once.

2. Insertion after sub-section (bb) of section 2 of the Act 6 of 1935 – The following Sub-section (bbb) shall be added after the Sub-section (bb) of section 2 of the Jharkhand co-operative societies Act, 1935, namely “Cooperative Society” means a society registered under this Act.

3. Amendment in Sub-section (e) of Section - 2 of the Act 6 of 1935 – Sub-section (e) of Section 2 of the Jharkhand Co-operative Societies Act, 1935 shall be substituted by the following, namely–

(e) “Board” means Board of Directors or Governing Body or Managing Committee, by whatever name called, to whom the direction and control of the management of the affairs of a Co-operative Society is entrusted to;

4. Amendment in Sub-section (ff) of section-2 of the Act-6 of 1935 –Sub-section (ff) of section-2 of the Jharkhand Co-operative Societies Act, 1935 shall be substituted by the following namely- “Multipurpose Cooperative Society” means a Primary Society, the object of which is to provide various services related to credit, business, industry, consumer durables to its members.

5. Amendment in Sub-section (gg) of section-2 of the Act-6 of 1935 –Sub-section (gg) of section-2 of the Jharkhand Co-operative Societies Act, 1935 Shall be substituted by the following namely-“**office bearer**” means a president, vice president, chairperson, vice chairperson, secretary or treasurer of a co-operative society and includes any other person to be elected by the Board of any co-operative society;

6. Amendment in Sub-section (ggg) of section-2 of the Act-6 of 1935 –Sub-section (ggg) of section-2 of the Jharkhand Co-operative Societies Act, 1935 Shall be substituted by the following namely- “Primary Society” means a registered society whose membership consists exclusively of individuals and self help groups.
7. Amendment in Sub-section (gggg) of section-2 of the Act-6 of 1935 –Sub-section (gggg) of section-2 of the Jharkhand Co-operative Societies Act, 1935 shall be substituted by the following namely- “Primary Agriculture Credit Society”- (1) The Primary object or principal business of which is to provide financial accommodation to its members for agricultural purposes or for purposes connected with agricultural activities (including the marketing of crops; and includes a Multipurpose Cooperative Society.
8. Amendment in Sub-section (o) of section-2 of the Act-6 of 1935 –Sub-section (o) of section-2 of the Jharkhand Co-operative Societies Act, 1935 Shall be substituted by the following namely- “Central Cooperative Society” means a Co-operative Society which is different from Federation and Union and which has any other Co-operative Society, and if the by-laws so provided, individuals as its members.
9. Insertion after sub-section (t) of section 2 of the Act 6 of 1935 – The following Sub-section (u) shall be added after the Sub-section (t) of section 2 of the Jharkhand co-operative societies Act, 1935, namely “**General Body**” means all the members or delegates of all the members of that co-operative society collectively;
10. Insertion after sub-section (u) of section 2 of the Act 6 of 1935 – The following Sub-section (v) shall be added after the Sub-section (u) of section 2 of the Jharkhand co-operative societies Act, 1935, namely “**Authorised person**” means a person referred to as such in Section 45 (1) of the Jharkhand Co-operative Societies Act, 1935;
11. Insertion after sub-section (v) of section 2 of the Act 6 of 1935 – The following Sub-section (w) shall be added after the Sub-section (v) of section 2 of the Jharkhand co-operative societies Act, 1935, namely “**State level Co-operative Society**” means a co-operative society having its area of operation extending to the whole of state and defined as such in the Jharkhand Co-operative Societies Act, 1935;
12. Insertion after Sub-section (w) of section 2 of the Act 6 of 1935 – The following Sub-section (x) shall be added after the Sub-section (w) of Sub-section 2 of the Jharkhand Co-operative Act, 1935 namely “**Functional Directors**” means functional executive directors of the society specified as per rules or Bye-laws of that co-operative society;
13. Amendment in Sub-section (1) and Sub-section (2) of section 13 A of the Act 6 of 1935 –Sub-section (1) and Sub-section (2) of section 13 A of the Jharkhand Co-operative Societies Act, 1935 shall be substituted by the following, namely:–

- (1) It shall be the duty of the State Government to encourage and promote the voluntary formation, autonomous functioning, democratic member-control and member-economic participation, professional management of Co-operative Societies in the State and to take such steps in this direction as may be necessary.
- (2) To encourage and promote the co-operative society with provisions of sub-section (1), the State Government if it deems necessary, may –
 - (a) With a view to aid the growth of a co-operative society in general or of any class of co-operative societies subscribe directly to the share capital of a co-operative society;
 - (b) assist in the formation and augmentation of the share capital of a co-operative society;
 - (c) give loans or make advances to a co-operative society or guarantee repayment of principal and payment of interest on debentures issued by a co-operative society or guarantee repayment of principal and payment of interest on loans or advances to a co-operative society.

14. Amendment in Sub-section (2) of section 14 of the Act 6 of 1935 – Sub-section (2) of section 14 of the Jharkhand Co-operative Societies Act, 1935 shall be substituted by the following, namely:–

The management of registered society shall be vested in a managing committee constituted in accordance with the provisions of this Act and rules/ Bye-laws of the society made under this Act. Provided that the Maximum number of directors of a co-operative society shall not exceed twenty-one;

Provided that at least 50 Percent seat of managing board shall be reserved for the women members. Out of which two seats shall be reserved for the Scheduled Castes or Scheduled Tribes women in the board of every Co-operative Society consisting of individuals as members and having members from such class or category of persons. The seats so reserved shall be filled up from amongst the members of scheduled castes or scheduled tribes women members either by election or /and by co-option.

This provision shall apply to all societies from the primary society and up to the Apex society. Provided further that such reservation in primary society and up to the Apex society shall be governed by the rules made under this Act for this purpose.

15. Renumbering of Sub-section 4 of section 14 of the Act 6 of 1935 – Sub-section 4 of section 14 shall be renumbered as Sub-section (4A) of section 14 of the Jharkhand Co-operative Societies Act, 1935.

16. Insertion of Sub-section (4B) after Sub-section (4) of section (14) of the Act 6 of 1935 – Sub-section (4B) shall be added after Sub-section (4) of section (14) of the Jharkhand Co-operative Societies Act, 1935 by the following, namely:

- (4B) Notwithstanding anything contained in any provision of this Act, or rules framed thereunder or the bye-laws of any Co-operative Society, persons having experience in the field of banking,

management, finance or specialization in any other field relating to the objects and activities undertaken by the co-operative society may be co-opted to the board of the society. Provided that the number of such co-opted members shall not exceed two and that number shall be in addition to the specified maximum number in the Sub-section 2.

Provided further that such co-opted members shall not have the right to vote in any election of the co-operative society in their capacity as such members or to be eligible to be elected as office bearers of the board.

Provided also that the **functional directors** of a co-operative society shall also be the members of the board and such members shall be excluded for the purpose of counting the total number of directors specified in the sub section 2.

17. Amendment in Sub-section (9) of section (14) of the Act 6 of 1935 – Sub-section (9) of section (14) of the Jharkhand Co-operative Societies Act, 1935 shall be substituted by the following, namely:-

Notwithstanding anything contained in any provision of rules or the bye-laws of any Co-operative Society, the election of a board shall be conducted before the expiry of the term of the board so as to ensure that the newly elected members of the board assume office immediately on the expiry of the office of members of the outgoing board.

The superintendence, direction and control of the preparation of electoral rolls for, and the conduct of all elections to a co-operative society shall vest in such an authority or body, as may be provided by the act or as per the rules or the bye-laws of the co-operative society.

Notwithstanding anything contained in any provision of rules or the bye-laws of any Co-operative Society the term of office of elected members of the board and its office bearers shall be five years from the date of election and the term of office bearers shall be conterminous with the term of the board.

Provided that the board may fill a casual vacancy on the board by nomination out of the same class of members in respect of which the casual vacancy has arisen, if the term of office of the board is less than half of its original term.

Provided further that if the term of the Board remains for more than half of its original term and if any vacancy arises for elected members or office bearers for any reason whatsoever, the Co-operative society shall fill the vacancy by special general meeting.

18. Amendment in Sub-section (10) of section (14) of the Act 6 of 1935 – Sub-section (10) of section (14) of the Jharkhand Co-operative Societies Act, 1935 shall be deleted.

19. Amendment in section (27) of the Act 6 of 1935 – Section (27) of the Jharkhand Co-operative Societies Act, 1935 shall be substituted by the following, namely:-

- (1) Member of a co-operative society shall exercise the rights of a member after he has made such payment to the society in respect of membership as may be prescribed in the rules or bye-laws of the society.

Provided that notwithstanding anything contained in any provisions of this Act, the member of a Co-operative Society shall exercise the right to vote at the election of members of the board of society only after ensuring minimum attendance, as required in the meetings convened for participation in management of the society and availing of minimum requisite services of the society as may be prescribed by the rules or the bye-laws of the society made under the act.

- (2) Every co-operative society shall provide access to every member to books, information and accounts of the co-operative society kept in regular transaction of its business with such member.
- (3) Every member of a co-operative society shall have the right to get all information/documents regarding books, information and accounts of the co-operative society kept in regular transaction of its business. The chief executive officer/manager of the co-operative society shall ensure access to the member to all required information/documents.
- (4) The members of any co-operative society shall have the right to get education and training related to co-operative as per the rules or byelaws made under any provisions of this act.

20. Insertion of chapter IV-A after chapter IV of the Act 6 of 1935 – Chapter IV-A shall be added to the Jharkhand Co-operative Societies Act, 1935 after chapter IV, namely –

Annual General Meeting and Annual Statement of Accounts of the Co-operative Society

32 (A) Annual General Meeting:-

- (1) Board of every Co-operative Society shall convene annual general meeting within six months from the closure of financial year, which shall deal with all or any of the matter listed below except those in relation to the election of members and office-bearer of the Board:-
- consideration of the annual statement of accounts presented by the Board for being filed before the Registrar.
 - consideration of annual report presented by the Board.
 - appointment and removal of statutory auditors and internal auditors,
 - consideration of the auditor's report and audited statement of accounts for being filed with the Registrar,
 - consideration of audit/special audit compliance report,
 - report on action taken on inquiry report under section 39, if any,
 - disposal of net surplus,
 - review of operational deficit, if any,

- (i) approval of the long term perspective plan and the annual operational plan,
 - (j) approval of the annual budget,
 - (k) creation of specific reserves and other funds.
 - (l) review of actual utilization of reserve and other funds,
 - (m) report on membership of the Co-operative Society in other Co-operative Societies.
 - (n) appeal of a person whose application for membership has been rejected or whose membership has been terminated by the board.
 - (o) remuneration payable to any Director, auditor or internal auditor in connection with his duties in that capacity or his attendance at related meeting,
 - (p) membership of the Co-operative Society in union/federation.
 - (q) collaboration with other organisation,
 - (r) amendment of bye-law,
 - (s) formulation of code of conduct for the Directors and office- bearers,
 - (t) note on admission and termination of members,
 - (u) dissolution of the co-operative Society.
 - (v) such other functions specified in the bye-laws.
- (2) In accordance with the provisions of sub-section (1), for the works specified under sub-section (2), the annual general meeting of the Co-operative Society shall be held at a time, date and place notified in accordance with the bye-laws and if the quorum is present, the Chairman of the Co-operative Society shall preside over the meeting.
- Provided that in the absence of Chairman, Vice Chairman, or in the absence of both Chairman and Vice Chairman, a person elected by the members from among themselves shall preside over the meeting.
- Provided further that in case of a Society, where the Managing Committee has been superseded under the provision of the Act, the Administrator shall be the Chairman of the General Meeting and in his absence a person nominated by him shall be the Chairman of the meeting.
- (3) The person presiding at the meeting shall conduct the proceedings in such manner as may be conducive to expeditious and satisfactory disposal of business and shall decide all points of order at the meeting.
 - (4) The quorum for a general meeting shall be one fifth of the total membership of the society or thirty whichever is less on the date of issue of the notice of the meeting.

- (5) If within an hour of the time schedule appointed for the meeting the quorum is not present, the meeting shall stand adjourned to a date not earlier than seven days and not later than twenty- one days:
- (6) No quorum shall be necessary for an adjourned meeting.
- (7) All questions before a general meeting shall be decided by a majority of votes and in the event of equality of votes, the Chairman of the meeting shall have a casting vote.
- (8) Voting by proxy shall not be allowed, but the Registrar may permit this to be done in the case of any particular registered society or class of registered societies.
- (9) Voting at a general meeting shall be done by show of hands and only in exceptional case voting by ballot may be resorted to if the Registrar so directs, on his own motion, or on the application filed by the society concerned.
- (10) The minutes of proceeding of general meeting shall be recorded in a book to be kept for the purpose and the minutes shall be signed by the person presiding at the meeting.
- (11) An appeal shall lie to the Registrar on all matters relating to procedure followed at any general meeting and his decision thereon shall be final.

32(B) Filing Annual statements of Accounts:- Co-operative Society shall file returns before the Registrar within six months of the end of every financial year which shall include following subjects:

- (a) Annual report of the activities.
- (b) Audited statement of accounts.
- (c) Plan to deal with the surplus as approved by general body.
- (d) List of the amendments done, if any, in the bye-laws of the Co-operative Society.
- (e) Declaration regarding date to the conduct of election, if due, and date for the holding of its general body meeting.
- (f) Any other information by the registrar in pursuance of any of the provisions of the act.

21. Amendment in section (33) of the Act 6 of 1935 – Section (33) of the Jharkhand Co-operative Societies Act, 1935 shall be substituted by the following, namely:-

Audit: (1) A Co-operative Society shall get its accounts audited by Auditor from a panel approved by Registrar, Co-operative Societies or the authority authorized by him, at least once in each financial year. Such auditor shall either be a Chartered Accountant within the meaning of the Chartered Accountants Act, 1949 or from the office of the Registrar.

- (2) The minimum qualification and experience of auditors and Chartered Accountants firm shall be determined from time to time. Only such auditor or Chartered Accountants firm shall be eligible for the audit of the accounts of Co-operative Society.

- (3) The audit of the accounts of every Co-operative Society shall be done by the auditor or Chartered Accountant firm, specified under sub-section(2), appointed by the General Body of Co-operative Society.
- (4) It shall be mandatory to audit the accounts of every Co-operative Society within six months from the end of the financial year.
- (5) Apex Co-operative Society, with the approval of general body shall compulsorily submit the audit report after the audit of the statement of accounts to the Registrar within thirty days so that the report may be placed in the Legislature through State Government in accordance with the procedure laid down by the State Government for this purpose.
- (6) It shall be the duty of the board to ensure that annual financial statements are prepared and presented for audit within forty-five days of closure of the financial year.
- (7) The remuneration of an auditor shall be fixed by the general body in terms with the audit fee fixed by the Registrar.

Provided that if audit is done by the auditor of the office of Registrar, the Co-operative Society shall pay the audit fee fixed by the Registrar.

- (8) Upon the demand of the auditor of a Co-operative Society, the present or former office-bearers, board members or employees of the Co-operative Society shall furnish-
 - (a) such information and explanation, as may be considered necessary, and
 - (b) each of the record, documents, books of accounts and vouchers of the Co-operative Society as are, in the opinion of the auditor, necessary to enable him to make the examination and report.
- (9) Where a Co-operative Society fails to get its annual account audited when due, Registrar shall get the accounts of the Co-operative Society audited within a period of ninety days from the date when the audit was due.
- (10) The cost of conducting such audit shall be borne by the Co-operative Society.

22. Insertion of section (33) (A) after section (33) of the Act 6 of 1935 – Section (33) (A) shall be added after section (33) to the Jharkhand Cooperative Societies Act, 1935 by the following, namely:-

33.(A) Special Audit – (1) A Co-operative Society dealing with funds from the Government or other external individual or institution may be subject to a special audit initiated by the Registrar at the request of such creditor or of his own motion with written specific order/direction.

(2) Special audit under Sub-section (1) shall be done by District Audit Officer/Senior level Audit Officers or any Committee of such officers under the control of Registrar.

- (3) Provided that where the special audit reveals serious mismanagement in the Co-operative Society, such costs may be recovered from the Co-operative Society or the persons responsible for the mismanagement.
- (4) Every special audit shall be completed and the report submitted to the Registrar within one hundred and twenty days of its commencement.
- (5) The special audit report shall contain a statement of :-
 - (a) every payment which appears to the auditor to be contrary to Act, rules or bye-laws of the Society,
 - (b) the amount of any deficiency, waste or loss which appears to have been caused by the gross negligence or misconduct of any person in the performance of duties,
 - (c) the amount of any sum received which ought to have been accounted for but is not brought into account by any person, and
 - (d) any asset or money, which any person related with the organization or management of the Co-operative Society or any former or present member of the Co-operative Society has misappropriated or fraudulently retained.
- (6) The Registrar shall, within a period of thirty days from the date of the receipt of the special audit report transmit copies of the same to –
 - (a) the applicant creditor,
 - (b) the cooperative society concerned, and
 - (c) direct the authorized officer to file proceedings of surcharge where necessary under section 40.

23. Insertion of section 33 (B) after section 33 (A) of the Act 6 of 1935 – Section 33 (B) shall be added after section 33 (A) to the Jharkhand Co-operative Societies Act, 1935

33 (B) Maintenance of accounts and records

- (1) Every Co-operative Society shall keep at its registered office the following accounts and records :-
 - (a) a copy of this Act with amendments made from time to time,
 - (b) the minutes book,
 - (c) registration certificate and a copy of the registered bye-laws and the amendments made from time to time with date of amendment.
 - (d) a copy of the authenticated byelaws of the federation/union of which it is a member and for each of its member Co-operative Societies.
 - (e) account of all sums of money received and expended by the Co-operative Society and their respective purposes.
 - (f) account of all purchases and sales of goods by the Co-operative Society,
 - (g) account of the assets and liabilities of the Co-operative Society.

-
- (h) a register showing total membership and the member wise use of various services,
- (i) a list of members with voting rights for the current year updated within thirty days of closure of the financial year,
- (j) copies of the board policies,
- (k) annual report, audit report, special audit report, inquiry report and their compliances.
- (l) copies of other laws and regulations to which the Co-operative Society is subject,
- (m) such other documents as are relevant to the functioning of the society provided that where a Co-operative Society has branch offices, accounts and records related to the branch, shall be available at the registered office for any period within twenty five days of the end of the financial year.
- (n) all other documents, register, circulars, etc. required in accordance with the provisions and circulars issued by NABARD, RBI and Registrar from time to time.
- (2) The books of accounts of every Co-operative Society together with supporting records and vouchers shall be preserved for such period as may be provided in the bye-laws subject to any other laws for the time being in force.
- 24.** Insertion in subsection (1) of section 40 of the Act 6 of 1935 – The following words shall be added in first line of subsection (1) of section 40 of the Jharkhand Cooperative Society Act, 1935 – The words “and special audit under section 33 (A)” after the words “audit under section 33”
- 25.** Amendment in Sub-section (1) of section 41 of the Act 6 of 1935 – Sub-section (1) of section 41 of the Jharkhand Co-operative Societies Act, 1935 shall be substituted by the following, namely:-
- (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no board shall be superseded or kept under suspension for a period exceeding six months;
- Provided that if in the opinion of the Registrar, the Board of any registered society, where the state government has contributed to the share capital, has provided loan, or financial aid provided has been on Government guarantee may be superseded or kept under suspension in case, it-
- (i) is persistently making defaults, or
- (ii) is negligent in the performance of the duties imposed on it by this Act, the Rules or the bye-laws, or
- (iii) committed any act prejudicial to the interest of the co-operative society or its members, or
- (iv) there is stalemate in the constitution or functioning of the Board; or
- (v) the authority or body as provided in the act, rules and bye-laws has failed to conduct elections in accordance with the provisions of the act:
- The Registrar may, after giving opportunity to the managing committee to state its objection, if any, by order, with reasons in writing, supersede the Board of the Co-operative society for a period

not exceeding six months and order that all or any of its members may be disqualified from being elected to the Board of the co-operative society for a period to be specified in the order, not exceeding five years. Registrar shall record every order passed under this section in writing and inform the concerned Co-operative society through registered post.

Provided further that the board of any such co-operative society shall not be superseded or kept under suspension where there is no government shareholding or loan or financial assistance or any guarantee by the government.

Provided that in case of co-operative society carrying on the business of banking, provisions of Banking Regulation Act, 1949 shall also apply.

Provided also that in case of co-operative society carrying the business of banking the maximum period of dissolution shall be of one year.

Provided that the dissolution of the Board of the co-operative society having banking operation shall be done in consultation with the Reserve Bank of India.

In case of supersession of a board, the Administrator so appointed shall provide every possible help to conduct the election. This arrangement shall be an interim arrangement and the Administrator shall hand over the management of the society to the new board after election within the prescribed period.

Provided that where government has not provided share capital or loan or financial assistance or any government guarantee and where the Co-operative Society fails to conduct elections before the expiry of the term of the board, the Registrar of the co-operative societies may order to convene a special general meeting of the members, for appointing an ad-hoc board for the purpose of conducting elections.

Provided that the outgoing members and office bearers of Board shall not be included in ad-hoc Board for the purpose of conducting elections.

Provided further that the term of ad-hoc board so appointed shall not exceed six months and the ad-hoc board so appointed shall provide every possible help to the Co-operative society to conduct the election. This arrangement shall be an interim arrangement and such appointed ad-hoc board shall hand over the management of the society to the new board after election within the prescribed period.

- 26.** Amendment in Sub-section (2) of section 41 in the Act 6 of 1935 – Sub-section (2) of section 41 of the Jharkhand Co-operative Societies Act, 1935 shall be substituted by the following, namely:- where the Registrar while proceeding to take action under Sub-section (1) is of opinion that suspension of the Board is necessary in the interest of the co-operative society, he may suspend the Board which shall

thereupon cease to function and make such arrangement as he thinks proper for the management of the affairs of the co-operative society till the proceedings under Sub-section (1) are completed.

Provided that if the Board so suspended is not superseded it shall be reinstated after six months and the period during which it has remained suspended shall count towards its term.

27. Amendment in Sub-section (3) of section 41 of the Act 6 of 1935 – Sub-section (3) of section 41 of the Jharkhand Co-operative Societies Act, 1935 shall be substituted by the following, namely:-

(3) When any Co-operative society is under supersession under Sub-section (1), the Registrar shall appoint an Administrator to conduct the affairs of the society. The Administrator appointed under sub-section (1), shall take necessary action for the election of the Board of Co-operative society within the specified period and shall hand over the management to elected Board.

Provided that the Registrar shall have the power to change the administrator during the period of supersession.

28. Amendment in Sub-section (4) of section 41 of the Act 6 of 1935 – Sub-section (4) of section 41 of the Jharkhand Co-operative Societies Act, 1935 shall be substituted by the following, namely:-

(4) The administrator appointed under sub-section (3) shall get remuneration, as may be fixed by the Registrar, as he deems fit to carry on the business of the co-operative society. The remuneration so fixed shall be payable from the accounts of co-operative society.

Provided that Administrator appointed under sub-section (3) shall work as per the service conditions laid down by the Registrar and shall perform all the duties and carry on responsibilities assigned to the Board under this act, rules and the bye-laws.

29. Amendment in section 42 of the Act 6 of 1935 – Section 42 of the Jharkhand Co-operative Societies Act, 1935 shall be substituted by the following, namely:-

Winding up order. – The Registrar may, by notification, order a registered society to be wound up if –

- (a) on receipt of a request for the winding up of the society by, special resolution passed by three-fourth of the members of the society,
- (b) after an inquiry has been held under section 35 or an inspection made under section 34, section 36 or section 37, the Registrar is of the opinion that winding up of the society is necessary in the interest of members, or
- (c) if a society has not commenced working after registration or has ceased working.
- (d) if the number of the members of the society has been reduced to less than ten contrary to the condition of registration.

But such order can only be passed after giving a notice of one month and providing opportunity of hearing to the shareholder members and persons/institutions having interest in the society.

- 30.** Amendment in Sub-section (1) of section 43 of the Act 6 of 1935 – The sub-section (1) of section 43 of the Jharkhand Co-operative Societies Act, 1935 shall be substituted by the following, namely:-

43 (1) Appeal against the order of winding up - Any member of a society or person/institution having interest in it, in respect of which an order under section 42 has been passed may, within two months from the date of the publication of such order in the official Gazette, appeal to the State Government against such order.

- 31.** Amendment in Section – 44AK of the Act 6 of 1935 – Section 44AK of the Jharkhand Co-operative Societies Act, 1935 shall be substituted by the following, namely–

Division, amalgamation, merger, compromise, etc. – (1) No order sanctioning a scheme of compromise or arrangement or of amalgamation or merger or reconstruction or of division or transfer of assets and liabilities of a Co-operative Bank shall be made without the previous sanction in writing of the Reserve Bank.

(2) Where an order of moratorium has been made by the Central Government under sub-section (2) of section 45 of the Banking Regulation Act, 1949(10 of 1949) in respect of a Co-operative Bank, the Registrar, with the previous approval of the Reserve Bank in writing may during the period of moratorium, prepare a scheme,-

- (i) for the re-construction of the Co-operative Bank; or
- (ii) for the merger of the Co-operative Bank, or
- (iii) for its amalgamation with any other Co-operative Bank (herein referred to as the transferee Bank).

(3) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act where a Co-operative Bank being an insured bank within the meaning of the Deposit Insurance Corporation Act, 1961(47 of 1961) is amalgamated or merged or in respect of which a scheme of compromise or arrangement or of reconstruction has been sanctioned and the Deposit Insurance Corporation has become liable to pay to the depositors of the insured bank, under sub-section (2) of section 16 of the Act, the bank with which such insured bank is amalgamated or merged or, the new Co-operative Bank formed after such amalgamation or, as the case may be, the insured bank or the transferee bank shall be under an obligation to repay the Deposit Insurance Corporation in the circumstances, to the extent and in the manner referred to in section 21 of that Act.

- 32.** Amendment in section-44AN of the Act-6 of 1935 –Section-44AN of the Jharkhand Co-operative Societies Act, 1935 shall be substituted by the following namely-

Repayment to Deposit Insurance Corporation. – Where a Co-operative Bank, being an insured bank within the meaning of Deposit Insurance Corporation Act, 1961 (47 of 1961) is wound up or is taken into liquidation and the Deposit Insurance Corporation has become liable to pay to the

depositors of the insured bank under sub-section (1) of section 16 of that Act, the liquidator shall be under an obligation to repay the Deposit Insurance Corporation in the circumstances to the extent and in the manner referred to in section 21 of that Act.

33. Amendment in section 44 AU of the Act 6 of 1935 – The Section 44 AU of the Jharkhand Co-operative Societies Act, 1935 shall be substituted by the following, namely:-

Notwithstanding anything contrary to or inconsistent with any provision contained in any other chapter of this Act or Rules framed under bye-laws of any registered society or order issued under the provision of this chapter shall have overriding effect.

34. Amendment in sub-section (21) of section 44 AV of the Act 6 of 1935 – The sub-section (21) of section 44 AV of the Jharkhand Co-operative Societies Act, 1935 shall be substituted by the following, namely:-

There shall not be any common Cadre of Staff in Short Term Co-operative Credit Structure Society and the Cadre System shall be abolished forthwith.

35. Amendment in section 45 (1) (a), Section 45 (1) (b) and Section 45 (2) of the Act 6 of 1935 – Section 45 (1) (a), Section 45 (1) (b) & Section 45 (2) of the Jharkhand Co-operative Societies Act, 1935 shall be substituted by the following, namely:-

(45) Offences and Penalties – (1) It shall be an offence under this Act if-

- (a) a Co-operative society or an officer or member thereof wilfully files a false return or furnishes false information, or any person wilfully does not furnish any information required from him by a person authorised in this behalf under the provisions of this Act;
 - (b) any person wilfully or without any reasonable excuse disobeys any summons, requisition or lawful written order issued under the provisions of this Act;
 - (c) any employer who, without sufficient cause, fails to pay to a Co-operative society, amount deducted by him from its employee within a period of fourteen days from the date on which such deduction is made;
 - (d) any officer or custodian who wilfully fails to handover custody of books, accounts, documents, records, cash, security and other property belonging to a Co-operative society of which he is an officer or custodian, to an authorised person; and
 - (e) any person indulges in corrupt practices before, during or after the election of the office bearer or member of the Board of the Co-operative society.
- (2) Any offence under Sub-section 1 of this section shall be punishable with imprisonment for a period which may extend up to one year or with a fine which may amount to rupees two thousand or both.

Provided that where a person is guilty of misappropriation, fraud, breach of trust, cheating or any other act involving moral turpitude, resulting in a loss to the Co-operative society, he shall also be punishable under the relevant provisions of the Indian Penal Code, 1860.

36. Amendment in Sub-section (2) of section 47 of the Act 6 of 1935 – Sub-section (2) of section 47 of the Jharkhand Co-operative Societies Act, 1935 shall be substituted by the following, namely:-

(2) Every offence under this Act except the offence under sub-section (1) (c) of section 48 shall, for the purpose of the code of criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) be deemed to be cognizable.

37. Amendment in Sub-section (1) of section 66 (B) of the Act 6 of 1935 – Sub-section (1) of section 66 (B) of the Jharkhand Co-operative Societies Act, 1935 shall be substituted by the following, namely:-

66 B (1). Personnel policy of Co-operative Societies – Co-operative Societies shall have autonomy in the formulation of policy regarding the posts, their numbers and the procedure for recruitment of the personnel thereof. Subject to provisions of byelaws and personnel policy, co-operative society shall prescribe the following among others:-

- (1) eligibility, age and experience,
- (2) pay scale and other emoluments,
- (3) procedure of recruitment,
- (4) service condition, and
- (5) disciplinary policy to be adopted.

38. Amendment in Sub-section (2) of section 66 (B) of the Act 6 of 1935 – Sub-section (2) of section 66 (B) of the Jharkhand Co-operative Societies Act, 1935 shall be substituted by the following, namely:-

(2) any appointment made in contravention of the provisions of the byelaws and the personnel policy shall be void and salary and other allowances paid if any, shall be recoverable under section 40.

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
बी० बी० मंगलमूर्ति,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।
